भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 133*

जिसका उत्तर मंगलवार, 26 जुलाई, 2016 को दिया जाना है।

हाइब्रिड कारें

133* श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी:

श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 2020 तक सड़कों पर 60 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने के लिए फेम इंडिया (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया) योजना को कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार विनिर्माता कंपनियों को ₹13000 की राजसहायता और ग्राहकों को 50 प्रतिशत उत्पाद शुल्क छूट दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त वाहनों का निर्माण करने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान विनिर्मित और बेचे गए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या कितनी है और कंपनियों को राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ङ) इन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के विपणन हेतु और इन प्रदूषण रहित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता हितैषी वातावरण के निर्माण हेतु सरकार और भारतीय कार विनिर्माताओं द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री अनंत ग. गीते)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

****

विवरण

"हाइब्रिड कारें" के बारे में श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी और श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा दिनांक 26.07.2016 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 133* के भाग (क) से (ङ) तक के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): जी, हां। भारत सरकार ने फेम-इंडिया (भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण) स्कीम अधिसूचित की है। इस स्कीम के चरण-I को ₹795 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय से अप्रैल, 2015 से प्रारंभ कर 2 वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की अवधि में कार्यान्वित किया जा रहा है। ₹75 करोड़ की प्रारंभिक राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में आबंटित की गई थी और ₹122.90 करोड़ चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आबंटित किए गए हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के तहत वर्ष 2020 तक 60-70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करना भारत सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।

(ग): इस स्कीम के अंतर्गत क्रेताओं (अंतिम प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं) को शुरुआती कम खरीद मूल्य पर मांग प्रोत्साहन उपलब्ध होगा ताकि इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के क्रेता वाहन/प्रौद्योगिकी की किस्म पर निर्भर करते हुए इन्हें व्यापक रूप से अंगीकार करने में समर्थ हो सकें। इस स्कीम में दिए गए मांग प्रोत्साहन का ब्यौरा भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (http://www.dhi.nic.in/) पर देखा जा सकता है। तथापि, किसी भी विनिर्माता कंपनी को कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। इसके अलावा, फेम इंडिया स्कीम के तहत उत्पाद शुल्क में 50% रियायत देने का कोई प्रावधान नहीं है। इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों का विनिर्माण करने वाले विभिन्न मूल उपकरण विनिर्माताओं के नाम **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(घ): जैसा कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (सिआम) और सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) द्वारा सूचित किया गया है, गत दो वर्षों के दौरान हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के कुल उत्पादन तथा कुल बिक्री का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	कुल उत्पादन (संख्या)	कुल बिक्री (संख्या)
2014-15	17,107	16,513
2015-16	71,909	65,244

चूंकि, फेम इंडिया स्कीम 01 अप्रैल, 2015 से कार्यान्वित की गई है, अतः विभिन्न पंजीकृत मूल उपकरण विनिर्माताओं से मांग प्रोत्साहन के लिए इस विभाग में प्राप्त दावों का ब्यौरा और 30 जून, 2016 के पश्चात् उन दावों के एवज में उनको जारी की गई प्रोत्साहन राशि का संक्षिप्त विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ङ): सरकार इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए टेक्नालॉजी प्लेटफार्म, चार्जिंग अवसंरचना, प्रायोगिक परियोजना और राष्ट्रीय कार्यशालाओं, जिनमें राज्य के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया है, का आयोजन करते हुए दीर्घकालिक क्रियाकलाप चला रही है। इन कार्यशालाओं में, राज्यों को (i) समर्थकारी वातावरण सृजित करके, (ii) चार्जिंग अवसंरचना सृजित करके, (iii) विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं प्रस्तुत करके, (iv) सड़क कर तथा वैट में रियायत प्रदान करके (v) आयोजना अनुमति एवं भवन उपनियम में चार्जिंग अवसंरचना के लिए प्रावधान करके देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उपाय करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

******

अनुबंध-I

दिनांक 26.07.2016 का लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 133*

i. महिन्द्रा रेवा इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रा. लिमिटेड

ii. इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड

iii. मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड

iv. हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रा. लिमिटेड

v. टोयोटा किर्लोसकर मोटर प्रा. लिमिटेड

vi. लोहिया ऑटो इंडस्ट्रीज

vii. एम्पेयर व्हीकल्स प्रा. लिमिटेड

viii. एवन साइकिल्स लिमिटेड

ix. वोल्वो इंडिया प्रा. लिमिटेड

x. क्रिस मोटर्स

xi. अजन्ता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड

xii. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड

अनुबंध II

बेचे गए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या जिनके लिए विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 और 2016-17 (जून, 2016 तक) के दौरान मांग प्रोत्साहन जारी किया गया।

मूल उपकरण विनिर्माता का नाम	वाहन का प्रकार	वाहनों की संख्या			जारी किया गया कुल मांग प्रोत्साहन (₹)
		2015-16	2016-17 (जून, 2016 तक)	योग	
महिन्द्रा रेवा इलेक्ट्रिकल प्रा. लिमिटेड	चौपहिया इलेक्ट्रिक	753	76	829	10,27,96,000
इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड	दुपहिया	2411	499	2910	2,18,25,000
मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड	चौपहिया मध्यम हाइब्रिड	30157	8610	38767	50,39,71,000
हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रा. लिमिटेड	दुपहिया	12039	1718	13757	10,45,46,000
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्रा. लिमिटेड	चौपहिया पूर्ण हाइब्रिड	1023	148	1171	8,19,70,000
लोहिया ऑटो इंडस्ट्रीज	दुपहिया	99	24	123	9,22,500
एम्पेयर व्हीकल प्रा. लिमिटेड	दुपहिया	234	60	294	22,05,000
एवन साइकिल्स लिमिटेड	दुपहिया	628	48	676	50,70,000
वोल्वो बसेज इंडिया प्रा. लिमिटेड	हाइब्रिड बस	0	0	0	0
क्रिस मोटर्स	दुपहिया	96	54	150	11,25,000
अजन्ता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड	दुपहिया	2034	0	2034	1,52,55,000
महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड	चौपहिया इलेक्ट्रिक	0	0	0	0
योग		**49474**	**11237**	**60711**	**83,96,85,500** अथवा **83.97** करोड़